E Learning Study Material

By Prof YADWENDRA SINGH

MAHARAJA COLLEGE ARA

BA PART TWO ECONOMICS HONS

PAPER THIRD

Evaluation of the New Industrial Policy

नई औद्योगिक नीति 1991 का उद्देश्य भारतीय औद्योगिक व्यवस्था को अनावश्यक नौकरशाही नियंत्रण के चंगुल मुक्त करना है। इस नीति के अनुसार सरकारी दर केवल उद्योगों पर नियंत्रण से बदलनी चाहिए ताकि बाद में कटौती करके इसे तेजी से विकसित होने में मदद मिल सके।

प्रवेश बाधाओं को दूर करना और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाना एवं साथ ही साथ यह नीति इसलिए भी लाइसेंस परमिट राज को समाप्त कर रही है जिसने निजी प्रयास और औद्योगिक विकास में बाधा उत्पन्न की है। अतः नई नीति सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए व्यापक रूप में विकसित करती है।

सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका रक्षा, रणनीतिक और पर्यावरण सम्बन्धी चिंताओ और उद्योग तक सीमित है। इस प्रकार नई नीति अधिक बाज़ार के अनुकूल है और इसका उद्देश्य जन्मजात औद्योगिक वातावरण में उपलब्ध उद्यमी प्रतिभा का सर्वोत्तम उपयोग करना है

विभिन्न विचारकों के अनुसार सरकार द्वारा घोषित नई औद्योगिक नीति देश के औद्योगिक विकास के इतिहास में एक साहसिक निर्णय है। यह अर्थव्यवस्था में बढ़ती दक्षता, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ और आधुनिकीकरण के उद्देश्य से मौजूदा औद्योगिक और वाणिज्यिक नीतियों को उदार बनाने के लिए भारत सरकार के वर्तमान आर्थिक सोच के अनुरूप है। अधिकांश औद्योगिक क्षेत्रों में लाइसेंस देने की प्रणाली का उन्मूलन, MRTP अधिनियम से परिसम्पत्ति मानदंड को वापस लेकर देश में Big is the Big सिंड्रोम से विराम नीतिगत पहल है जो देश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की संभावना है। NIP की एक नयी विशेषता प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने का प्रयास है।